क्र० सं०	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समिति (संख्या)
16.	मिजोरम	सूचित नहीं किया
17.	नागालैण्ड	22
18.	उड़ीसा	1060
19.	पाण्डिचेरी	81
20.	पंजाब	6009
21.	राजस्थान	5128
22.	सिक्किम	122
23.	तमिल नाडु	8158
24.	त्रिपुरा	80
25.	उत्तर प्रदेश	9845
26.	पश्चिम बंगाल	1395
	कुल:	72744

विवरण-IV

गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं में संगठित/पुनर्गठित की जा रही डेयरी सहकारी समितियों की संख्या।

क्र० सं०	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समितियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	180
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	50
4.	असम	414
5.	बिहार	900
6.	गुजरात	240
7.	हरियाणा	75
8.	जम्मू और कश्मीर	517
9.	मध्य प्रदेश	516
10.	महाराष्ट्र	714
11.	मणिपुर	60
12.	मेघालय	36
13.	मिजोरम	46
14.	नागालैण्ड	80
15.	उड़ीसा	375
16.	सिक्किम	155
17.	तमिल नाडु	489
18.	त्रिपुरा	13
19.	उत्तर प्रदेश	1000
20.	पश्चिम बंगाल	240
	कुल:	6232

सिंचित तथा असिंचित भूमि के क्षेत्रफल में अन्तर

3953. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचित भूमि तथा असिंचित भूमि के क्षेत्रफल तथा उसमें होने वाले औसत उत्पादन में भारी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में देश में सिंचित तथा असिंचित भूमि का पृथक-पृथक कितना-कितना क्षेत्रफल उपलब्ध था और उनकी उत्पादन क्षमता क्या-क्या थी तथा दोनों प्रकार की भूमि के उत्पादन में कितने प्रतिशत अंतर आंका गया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के भू-उपयोग आंकड़ों (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, देश में निवल बोए गए 142.51 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में से 50.10 मिलियन हैक्टेयर भूमि सिंचित थी तथा 92.41 मिलियन हैक्टेयर भूमि असिंचित। देश में 1995-96 में सिंचित भूमि के 52 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था जो देश में बोए जाने वाले कुल निवल क्षेत्र का लगभग 36.5 प्रतिशत है।

सिंचित और असिंचित भूमि में होने वाली औसत उपज में जो अंतर होता है वह फसलों और क्षेत्र की भिन्नता के कारण होता है। असिंचित भूमि में होने वाली उपज की तुलना में सिंचित भूमि में होने वाली उपज औसतन 70 से 120 प्रतिशत तक अधिक है।

Loss due to inefficient utilisation of wagon

3954. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what was the estimated loss to the Railways, zone-wise, during the last three years, year-wise, due to wasteful haulage and inefficient utilisation of wagon capacity and non-generation of earning capacity;

(b) what suggestions were given by the CAG and other consultative and advisory